DESU has also been advised to maximise generation at its stations, check pilferage reduce T&D losses, have better demand management and observe and enforce energy conservation measures.

(c) and (d) According to information received from Government of National Capital Territory of Delhi, DESU has made a few alternative proposals of a general character for privatisation of power distribution in Delhi which are at a preliminary stage of examination by the Government of Delhi.

CBI probe into oilfield award to Reliance Enron

1868. SHRI SATISH AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem appearing in the Business Standard of 17th June, 1996 captioned "CBI probes Oilfield Award to Reliance Enron"; and

(b) if so, the details thereof and the action proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BAALU): (a) Yes, Sir.

(b) CBI has initiated a preliminary enqiry in the matter.

आवास समस्या को सुलझाया जाना

1869. **श्री राधाकिशन मालवीय:**
श्री इकबाल सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में आवासीय समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण तथा शहरी दोनों स्तरों पर कोई प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कितने आवासों का निर्माण किया गया है और विभिन्न समुदायों के गरीब और पिछड़े लोगों को आबंटित किए जाने वाले मकानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सन् 2000 तक आवास समस्या को सुलझाने में सफल हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितने मकानों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटस्वरलू): (क) आवास राज्य का विषय है अतः विभिन्न आय वर्गों के लिए उनकी योजना प्राथमिकताओं तथा संसाधनों के अनुसार आवास योजना तैयार और कार्यान्वित करना मुख्यता राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार द्वारा विशेष लक्ष्य समूहों को आवास सुविधायें मुहैया कराने के लक्ष्य वाली अनेक योजनाऐं तैयार और कार्यान्वित करके राज्य सरकारों के इन प्रयासों में केवल योगदान दिया जाता है। ये योजनाऐं इस प्रकार है:

(I) शहरी निर्धनों के लिए नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत आश्रय उन्नयन;

(II) शहरों में फुटपाथ पर रहने वालों के लिए रैन-बसैरे तथा स्वच्छता सुविधायें;

(III) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण आवास योजनाएं;

(IV) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित ग्रामीण निर्धनों, मुक्त किये गए बंधुआ मजदूरों तथा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अन्य लोगों के लिए इन्दिरा आवास योजना;

(V) आवास योजनाओं के कार्यान्यन के लिए राज्य अभिकरणों को हुडको के माध्यम से आवास वित्त उपलब्ध कराना।

(ख) शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्मित रिहायशी एककों की राज्य-वार संख्या, जैसा कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रबोधन के संबंध में बताया गया है, विवरण-I में दी गई है **(नीचे देखिए)**। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्मित रिहायशी एककों की राज्य-वार संख्या विवरण-II में दी गई है **(नीचे देखिए)**। हुडको ने पिछले पांच वर्षों अर्थात् 1991-92 से 1995-96 के दौरान शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लिए कुल 1473820 रिहायशी एककों के निर्माण की स्वीकृति दी है। राज्य-वार ब्यौरे विवरण-III तथा विवरण IV में दिए गए है **(नीचे देखिए)**।